

कौशल विकास कार्यक्रमों का स्थानीय बाजारों में स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों के विस्तार में योगदान – रीवा संभाग के संदर्भ में

शिवम अग्रवाल^{1*} | डॉ. मनीष कुमार शुक्ला²

¹शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.).

²प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.).

*Corresponding Author: shivamag1993@gmail.com

Citation: शिवम अग्रवाल, & मनीष कुमार शुक्ला. (2025). कौशल विकास कार्यक्रमों का स्थानीय बाजारों में स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों के विस्तार में योगदान – रीवा संभाग के संदर्भ में. *International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science*, 07(04(II)), 91–94.

सार

रीवा संभाग में कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए सक्षम बनाना है। आधुनिक बाजार व्यवस्था में तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, आजीविका मिशन एवं आईटीआई संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण निरंतर संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से लाभान्वित युवा स्थानीय बाजारों में विविध सेवाओं एवं उत्पाद-आधारित लघु उद्यमों की स्थापना कर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं। रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं द्वारा स्थापित उद्यमों ने स्थानीय स्तर पर रोजगार, उत्पादन क्षमता और बाजार विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कौशल विकास कार्यक्रमों ने न केवल युवाओं में उद्यमिता का विस्तार किया है, बल्कि स्थानीय बाजारों में मांग-आपूर्ति संरचना को संतुलित करते हुए आर्थिक विकास को नई दिशा दी है। यद्यपि अवसर-संरचना, पूंजी की कमी, विपणन की सीमाएँ जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, परंतु कौशल विकास कार्यक्रम आर्थिक प्रगति हेतु प्रभावी साधन के रूप में उभर रहे हैं।

शब्दकोश: कौशल विकास, उद्यमिता, स्वरोजगार, लघु उद्यम, रीवा संभाग, स्थानीय बाजार, आर्थिक विकास।

प्रस्तावना

आधुनिक व्यापारिक परिवेश में कौशल विकास को आर्थिक प्रगति का आधार माना जाता है। वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और प्रतिस्पर्धी बाजार परिस्थितियों ने कार्यबल की गुणवत्ता एवं दक्षता को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत जैसे विकासशील देश में कौशल विकास न केवल रोजगार निर्माण का माध्यम है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी साधन भी है। मध्यप्रदेश का रीवा संभागकृजिसमें रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली शामिल हैंकृविभिन्न सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और सीमित औद्योगिक अवसरों वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में युवा रोजगार हेतु महानगरों की ओर पलायन करते रहे हैं। ऐसे में कौशल विकास कार्यक्रम स्थानीय आर्थिक संरचना में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं।

रीवा संभाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षणों ने युवाओं में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न की है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे—इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्रामीण उद्यमिता, कंप्यूटर प्रशिक्षण, ब्यूटी एंड वेलनेस, कृषि—आधारित प्रसंस्करण, निर्माण कार्य, रिटेल प्रबंधन आदि में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान किए गए हैं। इन कौशलों ने युवाओं को बाजार की आवश्यकताओं को समझने, ग्राहकों का प्रबंधन करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य करने, तथा स्वयं के उद्यम स्थापित करने की दृष्टि से सक्षम बनाया है।

स्थानीय बाजारों में स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन तथा बाजार में उत्पाद—सेवा विविधता प्रदान करते हैं। रीवा संभाग में कौशल विकास कार्यक्रमों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को *SHG* मॉडल के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया है। सिलाई—कढ़ाई, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, ब्यूटी सर्विसेज, रेडीमेड गारमेंट्स, मोबाइल रिपेयरिंग आदि कार्यों में महिलाओं और युवाओं ने अपने उद्यम स्थापित कर आर्थिक भागीदारी बढ़ाई है।

इन कार्यक्रमों ने तकनीकी ज्ञान के साथ—साथ प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान प्रणाली, विपणन रणनीतियों और उपभोक्ता व्यवहार की समझ भी विकसित की है। प्रशिक्षित युवाओं द्वारा स्थापित लघु उद्यम स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई गतिशीलता लेकर आए हैं। इससे एक ओर श्रमबल की उत्पादकता बढ़ी है तो दूसरी ओर स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हुआ है। अतः प्रस्तावना से यह स्पष्ट होता है कि कौशल विकास कार्यक्रम रीवा संभाग में आर्थिक विकास हेतु केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं और स्थानीय बाजारों में स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों की वृद्धि को निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं।

शोध उद्देश्य

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से निर्धारित किए गए हैं —

- रीवा संभाग में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के स्वरोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना।
- कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा लघु उद्यमों के विस्तार एवं स्थानीय बाजार संरचना में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।
- प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं की आर्थिक प्रगति, उद्यम स्थापना दर एवं व्यवसायिक स्थिरता का अध्ययन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध विधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़े रीवा संभाग के चयनित जिलों—रीवा, सतना, सीधी एवं सिंगरौली में संचालित कौशल विकास केंद्रों, प्रशिक्षकों, लाभार्थियों तथा स्थानीय उद्यमियों से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गए। इन प्राथमिक आंकड़ों में प्रशिक्षण की उपयोगिता, उद्यम स्थापना, आय में वृद्धि, बाजार हिस्सेदारी, पूंजी संरचना एवं चुनौतियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत सरकारी विभागों की रिपोर्टें, मध्यप्रदेश कौशल विकास बोर्ड के प्रकाशन, *PMKVY* की वार्षिक रिपोर्ट, जिला औद्योगिक केंद्र (*DIC*) अभिलेख, आर्थिक सर्वेक्षण, शोध लेख एवं पुस्तकों पर आधारित रहा। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के तुलनात्मक एवं अर्थ—विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा निष्कर्ष तैयार किए गए हैं।

विश्लेषण

रीवा संभाग में कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रभाव स्थानीय बाजारों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लाभार्थियों के कौशल स्तर में सुधार के साथ-साथ उद्यमिता की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं एवं महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत, ब्यूटी एंड वेलनेस, सिलाई केंद्र, किराना स्टोर, कृषि-आधारित प्रसंस्करण, रिटेल व्यवसाय, कंप्यूटर सेवाएँ, डिजिटल डिजाइनिंग एवं मोबाइल रिपेयरिंग में स्वरोजगार की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

विश्लेषण में पाया गया कि कौशल विकास कार्यक्रमों ने युवाओं में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के लिए आवश्यक तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताएँ विकसित की हैं। स्थानीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से ग्राहकों को बेहतर सेवाएँ और उत्पाद उपलब्ध होने लगे हैं। इससे एक ओर बेरोजगारी दर में कमी देखी गई है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिली है। इस प्रकार रीवा संभाग में कौशल विकास कार्यक्रमों से संधित प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी, स्वरोजगार अपनाने वाले व्यक्ति, स्थापित लघु उद्यमों की संख्या एवं औसत आय वृद्धि का विवरण सारणी क्रमांक 01 में प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है—

सारणी 1: रीवा संभाग में कौशल विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित एवं उद्यम स्थापित करने वाले व्यक्तियों की जानकारी (वर्ष 2021–2025)

क्र.	वर्ष	प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	स्वरोजगार अपनाने वालों व्यक्तियों की संख्या	स्थापित लघु उद्यम	औसत आय वृद्धि (%)
1.	2021	8,200	2,450	730	12%
2.	2022	9,600	3,100	890	15%
3.	2023	11,200	3,850	1,120	18%
4.	2024	12,750	4,600	1,350	21%
5.	2025	13,900	5,200	1,580	24%

स्रोत— मध्यप्रदेश, कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति प्रतिवेदन (2021–2025), भोपाल एवं जिला कौशल विकास कार्यालय, रीवा संभाग, वार्षिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार रिपोर्ट, जिला रीवा (मध्य प्रदेश), वर्ष 2021–2025।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रभाव वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में उद्यमिता की दर लगातार बढ़ी है। लघु उद्यमों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय बाजारों की संरचना अधिक मजबूत एवं प्रतिस्पर्धी हुई है। डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स को अपनाने से कई उद्यमियों ने अपने उत्पादों का बाजार विस्तार किया है। हालांकि पूंजी की कमी, ब्रांडिंग ज्ञान का अभाव, बाजार जोखिम एवं अवसंरचना संबंधी चुनौतियाँ अभी भी उपस्थित हैं, लेकिन कुल मिलाकर कौशल विकास कार्यक्रम ने रीवा संभाग की आर्थिक संरचना में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं।

शोध की समस्याएँ एवं सुझाव

शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि रीवा संभाग में कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के बावजूद कई समस्याएँ प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इनमें प्रमुख हैं— ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता में असमानता, प्रशिक्षण के बाद हैंडहोल्डिंग सपोर्ट की कमी, प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई, बाजार प्रतिस्पर्धा के प्रति सीमित समझ, डिजिटल कौशलों का अभाव तथा उद्यमिता परामर्श की कमी। कई लाभार्थी प्रशिक्षण के बाद भी उपयुक्त मार्गदर्शन के अभाव में उद्यम नहीं शुरू कर पाते हैं।

शोध समस्याओं के समाधान हेतु कुछ सुझावों को प्रस्तुत किया गया है, जैसे— प्रशिक्षण केंद्रों को आधुनिक उपकरणों एवं कुशल प्रशिक्षकों से सुदृढ़ करना, प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों के लिए मेंटरशिप एवं बाजार-लिंकज कार्यक्रम संचालित करना, बैंक ऋण एवं माइक्रोफाइनेंस तक पहुँच सरल बनाना, ऋण एवं युवा समूहों को बाजार से जोड़ने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना तथा नियमित फॉलोअप तंत्र विकसित करना शामिल हैं। इससे प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना में परिवर्तित हो सकेगा।

निष्कर्ष

अध्ययन के आधार पर स्पष्ट है कि रीवा संभाग में कौशल विकास कार्यक्रमों ने स्थानीय बाजारों में स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों के विस्तार को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया है। इन कार्यक्रमों ने युवाओं और महिलाओं को तकनीकी दक्षता, व्यवसायिक प्रबंधन क्षमता, डिजिटल ज्ञान एवं उद्यमिता कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप, स्थानीय स्तर पर नए उद्यमों की संख्या बढ़ी है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा और विविधता आई है। कौशल कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित युवाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की है बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान किया है। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि कौशल विकास रीवा संभाग के आर्थिक परिवर्तन का आधार बनकर स्थानीय बाजारों में सतत विकास एवं उद्यम विस्तार की संभावनाओं को मजबूत कर रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24, नई दिल्ली, भारत सरकार, 2024।
2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), संचालन दिशा-निर्देश, नई दिल्ली, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, 2022।
3. मध्यप्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड, राज्य कौशल विकास प्रकाशन 2024, भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, 2024।
4. जिला औद्योगिक केंद्र (DIC) रीवा एवं सांख्यिकीय प्रतिवेदन 2023, रीवा, उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2023।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), प्रशिक्षण एवं आजीविका अभिलेख 2024, नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2024।
6. इंडियन जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, वाणिज्य एवं प्रबंधन विषयक शोध लेख, खंड 14, अंक 2, 2023।

